नं. जेड-14014/2/2023-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3012849)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011,

दिनांक: 13.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मई, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को मई, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

संलग्नकः यथोक्त ।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथाउपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

मई, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में गुवाहाटी में दिनांक 3 से 4 मई, 2023 तक 'पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन' संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भूमि संसाधन विभाग, एलबीएसएनएए, मसूरी और असम सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन प्रणाली की कमियों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए प्रणालियों और संरचनाओं का प्रस्ताव करना था। पहली बार आयोजित इस प्रकार के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य की वर्तमान प्रथाओं और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, भूमि शासन मूल्यांकन फ्रेमवर्क, परंपरागत और स्वदेशी कानूनों संबंधी सत्रों को शामिल किया गया। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद, दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद; त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त परिषद, त्रिपुरा; लाई स्वायत्त जिला परिषद, मिजोरम; खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

2. सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 8 मई, 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के परियोजना क्षेत्र में "केक्टस की खेती और उसके आर्थिक उपयोग" पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र (आईसीएआरडीए), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों और भूमि संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

3. सचिव (भूमि संसाधन) ने दिनांक 26 मई, 2023 को विश्व बैंक की टीम और रिवार्ड कार्यक्रम के एनपीएमयू विशेषज्ञों के साथ विश्व बैंक सहायता प्राप्त "रेजुवीनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएन्स थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट (रिवार्ड) कार्यक्रम की समीक्षा की।

4. संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) ने दिनांक 4 मई, 2023 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत वार्षिक कार्य योजना, व्यय, एमआईएस के अद्यतनीकरण की स्थिति और पौधरोपण/बागवानी की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उन्होने राजस्थान राज्य में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दिनांक 12 मई, 2023 को जयपुर, राजस्थान

का दौरा किया और राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

5. संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) और वरिष्ठ अपर आयुक्त, भूमि संसाधन विभाग ने दिनांक 18 मई, 2023 को झांसी, उत्तर प्रदेश का दौरा किया और शूलहीन केक्टस की खेती पर निदेशक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के साथ विचार-विमर्श किया और बीज सामग्री की उपलब्धता का मूल्यांकन किया।

6. संयुक्त सचिव (भूमि विनियमन) ने दिनांक 11 मई, 2023 को एसोसिएशन ऑफ जियो-स्पेसियल इंडस्ट्रीज़ (एजीआई) द्वारा आयोजित "वॉट इज पॉवरिंग नैक्सट इन जियो-स्पेसियलः ईवेल्युएटिंग ट्रेंडस, ऑपरचुनिटीज़ एंड क्रॉसरोड्स इन पोस्ट-पॉलिसी लैंडस्केप्स" संबंधी ऑनलाइन संगोष्ठी में व्याख्यान दिया।

7. दिनांक 12 मई, 2023 को देहारादून में भूमि संसाधन विभाग और बी.एन युगांधर सेंटर फॉर रूरल स्टडीज़, एलबीएसएनएए, मसूरी द्वारा संयुक्त रूप से "पीयर लर्निंग ऑफ स्टेट ऑफिसियल्स ऑफ उत्तराखंड ऑन लैंड रिकॉर्डस मॉडर्नाइजेशन" पर एक कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में भूकर मानचित्रों का भू-संदर्भीकरण, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जरिए आधुनिक भू-सर्वेक्षण और विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन)-भू आधार संबंधी सत्र शामिल थे।

8. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत कुल 6382 {8214 (स्वीकृत) - 1832 (राज्यों को अंतरित)} परियोजनाओं में से अब तक 6376 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक 5841 परियोजनाओं की एंड लाइन मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

9. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

i. 6,22,530 गांवों के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
ii. 4,924 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
iii. 1,28,83,831 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।
iv. 4,081 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।
v. 3,326 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।